ISSN: 2277-7857

समकालीन हस्तक्षेप

साहित्य, समाज और संस्कृति की पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध-पत्रिका

वर्ष: 19, अंक: 1, जुलाई - सितंबर 2025

SJIF 2023 = 7.858

संपादक

डॉ. कपिल कुमार गौतम

वर्ष: 19, अंक: 1, जुलाई-सितंबर 2025

समकालीन हस्तक्षेप

साहित्य, समाज और संस्कृति की पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध-पत्रिका

'समकालीन हस्तक्षेप' त्रैमासिक शोध-पत्रिका में प्रकाशित शोध-पत्रों/ लेखों के माध्यम से व्यक्त किये गए विचार और स्थापनाएं लेखक के अपने हैं। उनके विचार और स्थापनाओं से संपादक मंडल अथवा प्रकाशक सहमत हों, यह जरुरी नहीं है। शोध-पत्रों/ लेखों में व्यक्त विचारों और स्थापनाओं के लिए सम्बन्धित लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे। विवाद की स्थिति में सभी मामले केवल रायसेन न्यायालय (मध्य प्रदेश) के अधीन होंगे।

इस शोध-पत्रिका के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। समीक्षा, लेखों तथा शोध-पत्रों में उद्धरण के अतिरिक्त, प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश का अनुवाद, प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रोनिक माध्यम से पुनर्प्रकाशित नहीं किया जा सकता। केवल सम्बंधित शोध-पत्र के लेखक ही अपने शोध-पत्र को अकादमिक तथा व्यक्तिगत उपयोग करने हेतु निर्बाध रूप से स्वतंत्र होंगे।

© Samkalin Hastakshep
July-September, 2025

Published by

INDIAN PUBLICATIONS
MIG - 108, Dr Hedgewar Colony,
Sanchi, Raisen, Madhya Pradesh
PIN – 464661 (India)

Email: issn22777857@hotmail.com
WhatsApp message: 09431109143
Website: www.hastakshep.co.in
www.facebook.com/hastakshep
www.instagram.com/hastakshep

संपादक

डॉ. कपिल कुमार गौतम
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
संघटक राजकीय महाविद्यालय, मीरापुर
बांगर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश – 246721

प्रबंध-संपादक

शेषनाथ वर्णवाल
कार्यकारी प्रबंधक, इंडियन पब्लिकेशन्स,
एम.आई. जी. - 108, हेडगेवार कॉलोनी,
साँची, रायसेन, मध्य प्रदेश – 464661

उप-संपादक

डॉ. अलका धनपत
पूर्व-विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग,
स्कूल ऑफ़ इंडियन स्टडीज़, महात्मा
गाँधी इंस्टिट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ़
मॉरीशस, मॉरीशस

डॉ. दीनानाथ
प्रोफेसर, हिंदी विभाग, सीएमपी डिग्री
कॉलेज, इलाहबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

डॉ. रजनी बाला अनुरागी
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. मोहन लाल चढ़ार
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं
पुरातत्त्व विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय
जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक,
मध्य प्रदेश

डॉ. राहुल सिद्धार्थ
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन
विश्वविद्यालय, साँची, मध्य प्रदेश

संपादक मंडल सदस्य

डॉ. प्रवीण कटारिया
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश

डॉ. हंसा दीप
लेक्चरार हिंदी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ टोरंटो, किंग्स कॉलेज सर्किल, टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा

डॉ. उमाशंकर कौशिक
असिस्टेंट प्रोफेसर (योगशास्त्र), के.जे. सोमैया इंस्टिट्यूट ऑफ़ धर्मा स्टडीज, पूर्वी मुंबई, महाराष्ट्र

डॉ. आमिर खान अहमद
असिस्टेंट प्रोफेसर (दर्शनशास्त्र), हरी-गायत्री दास महाविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी

डॉ. अनीश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

डॉ. विकास कुमार पाठक
समन्वयक, अनुवादिनी फाउंडेशन, ए.आई.सी.टी.ई., शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

डॉ. शरद पंडरीनाथ सोनवने
असिस्टेंट प्रोफेसर (अतिथि), कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र

डॉ. प्रतीक सागर
असिस्टेंट प्रोफेसर, शारदा स्कूल ऑफ़ डिजाईन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ग्रेटर नॉएडा

डॉ. अवधेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (अतिथि), हिंदी विभाग, डॉक्टर हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश

डॉ. सुनीता गुरुंग
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. लेखराम सेलोकर
पी-एच. डी. (बौद्ध अध्ययन), आनंद बुद्ध विहार, समता नगर, नागपुर, महाराष्ट्र

डॉ. लोकेश चौधरी
असिस्टेंट प्रोफेसर, योग विज्ञान विभाग, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, निंबाहेड़ा, राजस्थान

डॉ. अमित कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शिवाजी कॉलेज, राजा गार्डन, नई दिल्ली

डॉ. विपिन कुमार शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, श्री बाबू कलीराम राकेश राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखंड

डॉ. संदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ़ लीगल स्टडीज, मदरहूड विश्वविद्यालय, रूडकी, उत्तराखंड

डॉ. प्रत्युष प्रशांत
पी-एच.डी., सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. हिमांशु प्रभाकर
पी-एच.डी., समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड

अनुक्रम

वर्ष: 19, अंक: 1, जुलाई-सितंबर 2025

सम्पादकीय

1.	सामगान की दार्शनिकता: उपनिषदों के संदर्भ में	डॉ. सपना	9-12
2.	भारतीय चिंतन के संदर्भ में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ और आवश्यकता	प्रो. हर्षबाला शर्मा	13-17
3.	हिंदी में प्रगतिशील आलोचना की विकास यात्रा	कु. स्वाती	18-22
4.	डॉ. भीमराव अंबेडकर का प्रथम रायपुर छत्तीसगढ़ आगमन	डॉ. गणेश कुमार कोशले	23-26
5.	कैलाश बनवासी की कहानी संग्रह 'प्रकोप तथा अन्य कहानियाँ' में समस्याओं का चित्रण	डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, दुर्गेश कुमार	27-31
6.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं हिंदी साहित्य के मध्य संबंधों का एक पुनरावलोकन	साक्षी, प्रो. उषा पाठक	32-36
7.	भूमंडलीकरण के दौर में आत्मा रंजन की कविता में नारी चेतना	मुकेश कुमार	37-42
8.	भवानी प्रसाद मिश्र: मानवतावादी चेतना के अद्भुत साधक	डॉ. बालेन्द्र सिंह यादव	43-50
9.	हिंदी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का वैशिष्ट्य	भवानी सिंह गुर्जर, डॉ. रेखा शेखावत	51-54
10.	हिंदु विवाह की तानाशाही या आधुनिक मनुवाद – बीच बहस में डॉ. धर्मवीर	विजय लक्ष्मी	55-58
11.	'यह भी नहीं' उपन्यास में मध्यम वर्गीय संघर्ष और पारिवारिक विघटन: एक विश्लेषण	रणधीर आठिया	59-62
12.	समकालीन कविताः स्वरूप और विशिष्टताएँ	डॉ. सुरिन्द्र सिंह	63-68
13.	भारतीय भाषा, कला और संस्कृति का एकीकरण तथा शिक्षण में चुनौतियां	यामिनी, प्रो. स्वस्ति वर्मा	69-76
14.	राष्ट्रवादी इतिहास की अवधारणा और उपन्यासकार वृंदावनलाल वर्मा	गौरव कुमार	77-81
15.	मातृभाषा और भक्तिकालीन कवियों की भाषाई चेतना	सुकीर्ति तिवारी	82-86
16.	तीसरी सत्ता का संघर्ष	डॉ. अनीश कुमार	87-89
17.	भाषाई विमर्श: राष्ट्रभाषा वाया जनभाषा के प्रश्न	डॉ. प्रदीप कुमार	90-97
18.	भारत-नेपाल संबंध: चुनौतियां एवं संभावनाएं	कु. राजरानी जायसवाल, मोहन कुमार मिश्र	98-103

19.	सहजीवन: स्त्री-स्वातंत्र्य की चुनौतियाँ और पितृसत्ता का पुनर्संयोजन	डॉ. अर्चना रानी	104-108
20.	पटना (बिहार) में स्थित 3 राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं (INIs) के पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति: एक वेब अवलोकन आधारित तुलनात्मक अध्ययन	सदानंद कुमार चौधरी	109-113
21.	सरकारी और निजी विद्यालयों में बाल शिक्षा एवं खेल सुविधाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन	अंकिता राय, डॉ. (प्रो.) सुमन मिश्रा	114-117
22.	आयुर्वेदिक संदर्भ में वस्त्रों का प्राचीन और आधुनिक काल में योगदान: एक समीक्षात्मक अध्ययन	रेखा पटेल, प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह	118-124
23.	समकालीन हिन्दी उपन्यासों में पर्यावरण और आदिवासी जीवन	रिया श्रीवास्तव	125-127
24.	किशोरों के व्यवहार में आशावाद एवं सामाजिक संतुष्टि शीलगुणों में सहसंबंधात्मक अध्ययन: पिथौरागढ़ के डीडीहाट तहसील के संदर्भ में	विवेक आर्या, डॉ. नरेंद्र सिंह धारियाल	128-130
25.	आदिवासी दर्शन, संस्कृति और आजीविका में भूमि तथा वनों का महत्व	समीक्षा सिंह	131-136
26.	मुक्त प्रकृति के उन्मुक्त संवाहक : अनिल करंजयी	प्रीतिका गुप्ता	137-147
27.	नारी सशक्तिकरण और डॉ. राममनोहर लोहिया के विचार	जय सिंह वर्मा	148-150
28.	रीतिकालीन हिन्दी साहित्य में रामकथा	दर्शनकुमार प्रजापति	151-155
29.	व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया और मक्सिम गोर्की की माँ	कु. रोशनी	156-160
30.	हिंदी दलित साहित्य का उद्भव और विकास	डॉ. विक्रम कुमार	161-165
31.	गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीक: भारतीय ज्ञान का स्वर्णिम अध्याय	रत्नेश कुमार	166-169
32.	पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला भागीदारी: झारखण्ड (1947-2020 ई0)	महेश ठाकुर	170-174
33.	शिबू सोरेन और आदिवासी आंदोलन: संघर्ष से स्वराज तक	मसकलन तोपनो	175-179
34.	भारतीय समकालीन कला में अतियथार्थवादी अनुशीलन एवं चित्रकार	डॉ. हेमलता अग्रवाल, रंजना	180-185
35.	रेडियो कार्यक्रमों में नई मीडिया प्रौद्योगिकी का उपयोग	जयप्रकाश पंवार, डॉ. सुप्रिया रतूड़ी	186-192

सम्पादक की कलम से...

भारत में उदारीकरण के बाद आर्थिक नीतियों में निजीकरण को विकास का सबसे प्रभावी तरीका मान लिया गया है। देश में पिछले तीन दशकों से आर्थिक सुधारों के नाम पर निजीकरण को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। निजीकरण का मूल तर्क यह है कि सरकार का बोझ कम होगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और दक्षता बढ़ेगी। साथ ही यह भी माना जाता है कि निजी कम्पनियाँ प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाती हैं। इसलिए निजी क्षेत्र दक्षता, नवाचार और उत्कृष्ट प्रबंधन लेकर आएगा। इस सोच के कारण देश की अधिकतर आवश्यक सेवाओं को निजी कम्पनियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। संचार, ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग जैसे क्षत्रों में तो निजी कम्पनियों का आधिपत्य स्थापित हो गया है। निजीकरण आज केवल आर्थिक सुधार का एक माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न बनता जा रहा है। निजीकरण के समर्थक मानते हैं कि सरकार का काम कम्पनियाँ चलाना, व्यवसाय करना या सेवाएं प्रदान करना नहीं है। बल्कि उसका काम केवल नीतियाँ बनाना है। यह सिद्धांत तब बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर तब जब जनता के जीवन से जुड़ी सेवाओं को पूर्णत: निजी क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। निजी कम्पनियों की प्राथमिकता सेवाएं प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यवसाय करना होता है। ये कम्पनियाँ ग्राहक नहीं, 'उपभोक्ता' देखती हैं; नागरिक नहीं, 'बाजार' देखती हैं; सेवा नहीं, 'लाभ' देखती हैं। इस अंतर से यह स्पष्ट होता है कि निजी कम्पनियाँ अपने हित को सिद्ध करने के लिए करोड़ों लोगों के अधिकारों और आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकती हैं।

हाल ही में निजीकरण के प्रभाव को एयरलाइंस के मामले में भी देखा गया है। जब सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नए नियम लागू किए, ऐसे नियम जिनका उद्देश्य पायलटों को अत्यधिक थकान से बचाना था। नए प्रावधानों के अनुसार पायलटों को अनिवार्य रूप से अधिक आराम देना आवश्यक हो गया। सरकार के इस नियम के प्रभाव अनुरूप इंडिगो एयरलाइंस ने अचानक बड़े पैमाने पर हवाई यात्राएं रद्द कर दी। दूसरी कम्पनियों ने किराये में दस गुणा तक बढ़ोतरी कर दी। हवाई अड्डों पर फँसे यात्रियों की भीड़, लगातार बढ़ते किराए और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सीमित जवाबदेही ने संकेत दिया कि जब हवाई यातायात जैसी महत्वपूर्ण सेवा एक ही निजी कंपनी पर अत्यधिक निर्भर हो जाए, तो उसका कोई भी प्रशासनिक संकट पूरे देश को प्रभावित कर सकता है।

इसी प्रकार से दूरसंचार के क्षेत्र में जियो और एयरटेल जैसी दो कम्पनियों के प्रभुत्व से स्पष्ट है कि देश का लगभग पूरा डिजिटल ढाँचा इन्हीं पर टिका है। इस कारण ये कम्पनियाँ मनमाने ढंग से रिचार्ज के शुल्क में वृद्धि करती जा रही हैं। यदि किसी दिन जनता इनका विरोध करती है या सरकार इनके लिए कोई ऐसी नीति बनती है जिससे इन कम्पनियों को आपत्ति हो, तो ये पूरे देश की सेवाएं ठप कर सकती हैं। सोचिए यदि इंटरनेट बंद हो जाए, तो बैंकिंग, अस्पताल, शिक्षा, परिवहन, ई-शासन- सब कुछ ठहर जाएगा। यह स्थिति केवल असुविधा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जन-जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। इसी तरह ऊर्जा क्षेत्र में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। यदि कल किसी बड़ी निजी बिजली कंपनी, जैसे अदानी पावर, किसी स्तर पर चाहे तो देश की आपूर्ति रोक सकती है और देश के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो सकती है। पानी की सप्लाई रुक जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अस्पताल आपात स्थिति में पहुँच जाएँगे। ऐसा इसलिए क्योंकि निजी कम्पनियाँ मुनाफे और लागत की प्राथमिकताओं के अनुसार काम करती हैं, न कि सार्वजनिक हितों की अनिवार्यता के आधार पर। इन उदाहरणों को देखने के बाद एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है - क्या हम आवश्यक सेवाओं को कुछ निजी हाथों में देकर उसी दिशा में नहीं बढ़ रहे जिस दिशा में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को धकेला था? ईस्ट इंडिया कंपनी भी शुरू में एक 'व्यापारिक संस्था' ही थी। उसका उद्देश्य भी 'व्यापार को सरल बनाना' और 'दक्षता बढ़ाना' बताया गया था। पर धीरे-धीरे उसने व्यापार से प्रशासन, और प्रशासन से शासन तक का रास्ता तय कर लिया। कारण वही था- संसाधनों और अधिकारों का अत्यधिक केंद्रीकरण।